नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 339
दि. 12.04.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मुद्रा लोन घोटाले का खुलासा: बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी से उजागर हुआ करोड़ों का संगठित फर्जीवाड़ा

Lucknow से सामने आई इस सनसनीखेज खबर ने बैंकिंग व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। Uttar Pradesh Special Task Force ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक Nitin Chaudhary को Delhi से गिरफ्तार कर एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे करोड़ों रुपये के मुद्रा लोन हड़प लिए। यह मामला केवल एक बैंक अधिकारी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस गहरे नेटवर्क को उजागर करता है, जो सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर आर्थिक तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा था। जांच में सामने आया है कि आरोपी नितिन चौधरी, जो मूल रूप से Azamgarh का निवासी है, इस पूरे फर्जीवाड़े में सक्रिय भूमिका निभा रहा था और गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था।

एसटीएफ के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए गए हैं, जिनमें मोबाइल फोन, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड और नकदी शामिल है। ये सभी साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह घोटाला कोई सामान्य धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से तैयार किया गया अपराध था।

जांच एजेंसियों को मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर यह खुलासा हुआ है कि इस गिरोह ने 100 से अधिक लोगों के नाम पर फर्जी तरीके से ऋण स्वीकृत कराए। इसके लिए आधार और पैन कार्ड जैसे पहचान पत्रों के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। असली दस्तावेजों पर लगी तस्वीरों को हटाकर उनकी जगह अन्य व्यक्तियों की फोटो लगाई जाती थी, जिससे बैंकिंग सिस्टम को भ्रमित किया जा सके।

इसके बाद इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काल्पनिक कंपनियां बनाई जाती थीं और उन्हीं के नाम पर मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया जाता था। चूंकि इस प्रक्रिया में बैंक के अंदर से भी सहयोग मिल रहा था, इसलिए लोन स्वीकृति में कोई बड़ी बाधा नहीं आती थी। इस पूरे नेटवर्क में बैंकिंग प्रक्रिया की कमजोरियों का फायदा उठाया गया और नियमों को दरकिनार कर करोड़ों रुपये का गबन किया गया।

पूछताछ में यह भी सामने आया है कि जैसे ही लोन स्वीकृत होता था, उसकी राशि सीधे उन बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी, जिन्हें पहले से ही गिरोह के सदस्यों द्वारा फर्जी तरीके से खोला गया था। इन खातों के माध्यम से रकम को तेजी से निकाल लिया जाता था और फिर आपस में बांट लिया जाता था, जिससे ट्रांजैक्शन का पता लगाना मुश्किल हो जाता था।

इस मामले की जांच पहले से ही जारी थी और एसटीएफ अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस गिरोह का कथित मास्टरमाइंड Aamir Ehsan को फरवरी 2026 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से ही एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी थीं, और नितिन चौधरी की गिरफ्तारी उसी कड़ी का अहम हिस्सा मानी जा रही है।

इस घोटाले ने यह भी उजागर किया है कि सरकारी योजनाओं, विशेष रूप से Pradhan Mantri Mudra Yojana जैसी योजनाओं में किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा सकता है, यदि निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया में थोड़ी भी ढिलाई बरती जाए। मुद्रा योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, लेकिन इस तरह के घोटाले इस योजना की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए बैंकिंग सिस्टम में तकनीकी सुधार, सख्त ऑडिट और बेहतर निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। साथ ही, डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन पास कराने जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

एसटीएफ का कहना है कि इस मामले में अभी कई और खुलासे हो सकते हैं। जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि इस नेटवर्क में कई अन्य बैंक कर्मचारी, एजेंट और बिचौलिए भी शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने में मदद की।

इस घटना ने आम लोगों के बीच भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह सवाल उठता है कि यदि किसी के दस्तावेजों का इस तरह दुरुपयोग किया जा सकता है, तो उनकी व्यक्तिगत जानकारी कितनी सुरक्षित है। ऐसे में डेटा सुरक्षा और पहचान पत्रों के सुरक्षित उपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी हो गया है।

अंततः, यह मामला केवल एक घोटाले का खुलासा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि सरकारी योजनाओं और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए निरंतर सतर्कता जरूरी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को किस हद तक उजागर कर पाती हैं और दोषियों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है।

धमकी से दहला काशी: शंकराचार्य को मिली 'अतीक जैसा अंजाम' की चेतावनी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

वाराणसी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को उस समय गहरा झटका लगा, जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी मिलने की सनसनीखेज घटना सामने आई। यह केवल एक व्यक्ति विशेष को दी गई धमकी नहीं मानी जा रही, बल्कि इसके राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आयाम भी तेजी से उभर रहे हैं। काशी, जिसे सनातन परंपरा का केंद्र माना जाता है, वहां इस तरह की घटना ने आम जनमानस के बीच असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है।

घटना की शुरुआत एक ऑडियो क्लिप से होती है, जिसे शंकराचार्य के एक शिष्य ने पुलिस को सौंपा। इस ऑडियो में कथित तौर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने बेहद आपत्तिजनक और भयावह शब्दों का इस्तेमाल करते हुए शंकराचार्य को धमकी दी है कि उनका अंजाम भी माफिया डॉन अतीक अहमद जैसा होगा। यह संदर्भ अपने आप में गंभीर है, क्योंकि अतीक अहमद की हत्या देशभर में चर्चित और विवादित रही थी, जिसने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए थे।

जैसे ही यह मामला सामने आया, भेलूपुर थाना में तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला के अनुसार, ऑडियो क्लिप को तकनीकी विश्लेषण के लिए साइबर सेल को भेजा गया है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है, उसने किस माध्यम से यह संदेश भेजा और उसका मकसद क्या था। पुलिस का कहना है कि इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और हर संभावित एंगल से जांच की जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में भी हड़कंप मच गया है। शंकराचार्य की सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा की गई है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, खुफिया एजेंसियां भी इस मामले में सक्रिय हो गई हैं और यह जांच की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित साजिश तो नहीं है।

धार्मिक दृष्टि से देखें तो ज्योतिष पीठ का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। इस पीठ के शंकराचार्य न केवल धार्मिक मामलों में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी स्पष्ट राय रखते हैं। हाल के समय में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कई संवेदनशील मुद्दों पर मुखर रहे हैं, जिससे उनके समर्थकों के साथ-साथ विरोधियों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में इस धमकी को केवल एक व्यक्तिगत हमला मानना जल्दबाजी हो सकती है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश और चिंता देखने को मिल रही है। काशी के घाटों, मंदिरों और गलियों में चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि आखिर कोई इतना दुस्साहस कैसे कर सकता है कि देश के एक प्रमुख धर्मगुरु को खुलेआम धमकी दे दे। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में प्रभावशाली और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की सुरक्षा पर्याप्त है? खासकर तब, जब धमकी देने वाले खुलेआम ऐसे संदर्भों का इस्तेमाल कर रहे हों, जो हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं से जुड़े हों। यह न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि समाज में भय का वातावरण भी पैदा करता है। पुलिस की जांच अब तकनीकी साक्ष्यों पर केंद्रित हो गई है। कॉल डिटेल्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और अन्य डिजिटल ट्रेल्स के जरिए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर ली जाएगी और उसे गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया जाएगा।

इस बीच, शंकराचार्य के अनुयायियों और समर्थकों ने संयम बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि यह समय भावनात्मक प्रतिक्रिया देने का नहीं, बल्कि कानून पर भरोसा रखने का है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि इस घटना ने धार्मिक और सामाजिक स्तर पर एक गहरी चिंता पैदा कर दी है, जिसका असर आने वाले समय में भी महसूस किया जा सकता है।

अंततः, यह मामला केवल एक धमकी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक समरसता और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े व्यापक प्रश्नों को सामने लाता है। अब सभी की नजरें पुलिस और जांच एजेंसियों पर टिकी हैं कि वे इस रहस्य से कब पर्दा उठाती हैं और दोषी को सजा दिलाकर समाज में भरोसा बहाल करती हैं।

दिनदहाड़े गोलियों की गूंज से दहला मिर्जापुर: अधिवक्ता की हत्या ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शनिवार की सुबह उस वक्त दहशत में बदल गई, जब दिनदहाड़े एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली बन गई है। शहर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारूपुरा इलाके में हुई इस वारदात ने आम लोगों के मन में भय और आक्रोश दोनों को जन्म दिया है।

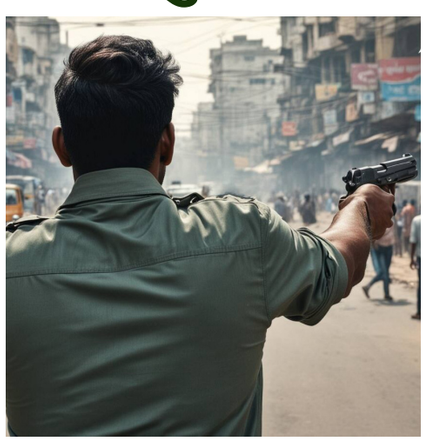

मृतक की पहचान वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह उर्फ रिंटू सिंह के रूप में हुई है, जो अपने क्षेत्र में एक जाने-पहचाने और सक्रिय विधि विशेषज्ञ माने जाते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना सुबह के समय हुई, जब अचानक बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने बेहद करीब से निशाना साधा, जिससे अधिवक्ता को बचने का कोई मौका नहीं मिला और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास के लोग सहम गए और कुछ ही देर में घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग स्तब्ध थे कि आखिर इतनी भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह खुलेआम हत्या कैसे हो सकती है। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए, जिससे पुलिस के सामने चुनौती और भी बढ़ गई है।

इस घटना के बाद परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, वे और भी ज्यादा चिंताजनक हैं। उनका कहना है कि राजीव सिंह ने पहले ही अपनी जान को खतरा बताया था और इस संबंध में पुलिस को शिकायत भी दी थी। परिजनों के मुताबिक, यह कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी उन पर दो बार जानलेवा हमले हो चुके थे। इसके बावजूद यदि समय रहते उचित कार्रवाई की जाती, तो शायद आज यह घटना टल सकती थी।

मृतक की पत्नी क्षेत्र की ग्राम प्रधान हैं, जिससे इस मामले को और भी संवेदनशील माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, पेशेगत विवाद या राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। हालांकि, अभी तक पुलिस ने किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया। बैद्यनाथ सिंह, जो कटरा कोतवाली के प्रभारी हैं, ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।

पुलिस ने इस मामले में विशेष टीमों का गठन किया है, जो विभिन्न एंगल से जांच कर रही हैं। मोबाइल कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट्स के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार कर कानून के कठघरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर आम नागरिक कितना सुरक्षित है? जब एक अधिवक्ता, जो कानून की समझ रखता है और जिसने पहले ही खतरे की आशंका जताई थी, वह भी सुरक्षित नहीं रह पाता, तो आम लोगों की स्थिति क्या होगी? यह सवाल केवल मिर्जापुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर एक व्यापक बहस को जन्म देता है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। कई लोगों का कहना है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे अब दिनदहाड़े भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से नहीं डरते।

गर्मी की वापसी से यूपी में बढ़ी तपिश, झांसी-प्रयागराज सबसे गर्म; एक हफ्ते में 40 डिग्री पार का अलर्ट

Uttar Pradesh में कुछ दिनों की ठंडी राहत के बाद अब मौसम ने अचानक करवट बदल ली है और गर्मी ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों को आने वाले दिनों में तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले एक सप्ताह के भीतर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है, जिससे गर्मी का असली दौर शुरू होने जा रहा है।

शनिवार को प्रदेश के मौसम में अचानक बदलाव दर्ज किया गया, जहां एक ही दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखी गई। हालांकि दिन के समय 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज पछुआ हवाओं ने कुछ हद तक राहत जरूर दी, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। India Meteorological Department के अनुसार, सोमवार से हवाओं की रफ्तार कम होने लगेगी और इसके साथ ही तापमान में लगातार वृद्धि का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में बारिश और आंधी देखने को मिली थी, जिसके कारण तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई थी। अप्रैल के महीने में नवंबर जैसी ठंडक का एहसास हो रहा था, लेकिन अब मौसम पूरी तरह बदल चुका है। जैसे-जैसे वातावरण शुष्क हो रहा है, वैसे-वैसे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

मौसम वैज्ञानिक Atul Kumar Singh के अनुसार, प्रदेश में पिछले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में औसतन 6 से 8 डिग्री तक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल तापमान सामान्य से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें लगातार वृद्धि होगी। प्रदेश में किसी भी सक्रिय मौसम प्रणाली के न होने के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की और बढ़ोतरी संभव है।

अगर जिलों की बात करें तो Jhansi और Prayagraj शनिवार को प्रदेश के सबसे गर्म जिले रहे, जहां अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा Varanasi और Orai में 37.4 डिग्री, Sultanpur में 37.2 डिग्री, जबकि Azamgarh और Ghazipur में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राजधानी Lucknow में भी गर्मी का असर अब साफ दिखने लगा है। यहां शनिवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 24 घंटे के भीतर 3.2 डिग्री की बढ़ोतरी को दर्शाता है। हालांकि इस दौरान तेज हवाओं के चलते लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन जैसे-जैसे हवाएं कमजोर होंगी, गर्मी का असर और अधिक महसूस होगा। सुबह के समय हल्की ठंडक और हवा की नरमी के कारण मौसम सुहावना रहता है, लेकिन दोपहर होते-होते तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण हालात बदल जाते हैं। दिन में धूप की तीव्रता लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों को बाहर निकलने में परेशानी होने लगी है।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में कोई बड़ा मौसम परिवर्तन नहीं होगा। यानी न तो बारिश की संभावना है और न ही कोई ठंडक देने वाली प्रणाली सक्रिय होगी। इस स्थिति में तापमान लगातार बढ़ता रहेगा और कई जिलों में 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर सकता है।

हालांकि वर्तमान में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम है, लेकिन बढ़ोतरी की गति को देखते हुए जल्द ही यह सामान्य स्तर को पार कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, 9 अप्रैल को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री था, जो 10 अप्रैल को बढ़कर 32.1 डिग्री और 11 अप्रैल को 35.3 डिग्री तक पहुंच गया। यह लगातार बढ़ती प्रवृत्ति आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का अचानक तापमान बढ़ना स्वास्थ्य के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। तेज धूप, लू और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना और दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचना जरूरी है। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में अब गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में तापमान और अधिक बढ़ेगा और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि लोग मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाएं।

अप्रैल में भी सर्दी का सितम: हिमाचल में बर्फबारी और शून्य के करीब पारा, मौसम ने चौंकाया

Shimla से आई इस खबर ने मौसम के बदले मिजाज को साफ कर दिया है। आमतौर पर अप्रैल के महीने में जहां देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी दस्तक दे देती है, वहीं Himachal Pradesh में सर्दी अब भी अपना असर बनाए हुए है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ठंडी हवाओं ने लोगों को हैरान कर दिया है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से काफी नीचे चल रहा है।

राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। Manali, Kullu और Chamba के ऊपरी क्षेत्रों में सफेद चादर बिछती नजर आ रही है, जिससे पर्यटकों को भले ही सर्दी का आनंद मिल रहा हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह स्थिति परेशानी का कारण बन गई है। दिनभर बादल छाए रहने और सूरज के दर्शन न होने से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

India Meteorological Department ने राज्य के पांच प्रमुख जिलों—Shimla, Kangra, Chamba, Mandi और Kullu—में खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे ठंड का अहसास और बढ़ जाएगा।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों जैसे Lahaul and Spiti, Kinnaur और चंबा के पांगी-भरमौर क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर लगातार हल्की बर्फबारी हो रही है। वहीं Hamirpur जैसे निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। इस असामान्य मौसम ने अप्रैल में भी ठंड का एहसास बरकरार रखा है।

तापमान के आंकड़े इस बदलाव की गंभीरता को साफ दर्शाते हैं। राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। कई स्थानों पर पारा एकल अंक में पहुंच गया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह शून्य के करीब या उससे भी नीचे चला गया है। Tabo में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस और Kukumseri में 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में असामान्य माना जा रहा है। अन्य प्रमुख स्थानों की बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री, सुंदरनगर में 11.9 डिग्री, भुंतर में 9.6 डिग्री, कल्पा में 2.4 डिग्री और मनाली में 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रदेश में सर्दी अभी पूरी तरह विदा नहीं हुई है।

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी पूर्वानुमान जारी किया है। 13 से 15 अप्रैल के बीच मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन 16 और 17 अप्रैल को एक बार फिर मौसम बिगड़ने के संकेत हैं। इसके लिए विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, जिससे प्रशासन और लोगों को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इस बीच, राज्य में बारिश के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। 10 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 142 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इतनी अधिक बारिश ने मौसम को अस्थिर बना दिया है और इसका असर जनजीवन के साथ-साथ कृषि और बागवानी पर भी पड़ रहा है।

किसान और बागवान इस असामान्य मौसम को लेकर चिंतित हैं। बेमौसम बारिश, ठंड और ओलावृष्टि का खतरा गेहूं की फसल और सेब जैसे फलदार पौधों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम की यही स्थिति बनी रही, तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।

सामान्य जनजीवन पर भी इस मौसम का प्रभाव साफ देखा जा रहा है। ठंडी हवाओं और बारिश के कारण लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो अप्रैल के महीने में असामान्य है। पर्यटक स्थलों पर भी मौसम की अनिश्चितता के कारण आवाजाही प्रभावित हो रही है।

कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज पूरी तरह से उलट नजर आ रहा है। जहां देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी बढ़ रही है, वहीं यहां सर्दी और बर्फबारी का दौर जारी है। यह बदलाव न केवल मौसम के पैटर्न में हो रहे परिवर्तनों की ओर इशारा करता है, बल्कि यह भी बताता है कि जलवायु में अस्थिरता किस तरह से हमारे दैनिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही है। आने वाले दिनों में मौसम किस दिशा में जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

चुनावी निष्पक्षता पर सियासी संग्राम: एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अखिलेश यादव के आरोपों से तेज हुई राजनीतिक बहस

जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए, तो उनके शब्दों में केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि चुनावी व्यवस्था पर गंभीर सवालों की गूंज सुनाई दी। उन्होंने जिस तरह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर धांधली का आरोप लगाया, उसने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में चुनावी माहौल धीरे-धीरे गरमाता जा रहा है और हर राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है।

अखिलेश यादव ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया के दौरान सुनियोजित तरीके से धांधली की है। उनका कहना था कि फार्म-7 के माध्यम से समाजवादी पार्टी के समर्थक वोटरों के नाम फर्जी तरीके से काटे गए। उन्होंने दावा किया कि इस पूरी प्रक्रिया में फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया और बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में छेड़छाड़ की गई। यह आरोप केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल खड़ा करता है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना होता है ताकि फर्जी नामों को हटाया जा सके और वास्तविक मतदाताओं को शामिल किया जा सके। लेकिन जब इस प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगें, तो लोकतंत्र की बुनियाद हिलने लगती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह संदेश जाता है कि कहीं न कहीं संस्थागत स्तर पर भी लापरवाही या पक्षपात हो सकता है।

इस पूरे मुद्दे को उन्होंने केवल तकनीकी या प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि एक साजिश करार दिया। उनका कहना था कि भाजपा ने जानबूझकर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के वोटरों को निशाना बनाया, क्योंकि यही वर्ग चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। उन्होंने दावा किया कि इस बार यही पीडीए समुदाय भाजपा को सत्ता से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अखिलेश यादव के इस बयान का एक राजनीतिक संदर्भ भी है। समाजवादी पार्टी लगातार यह दावा करती रही है कि वह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की राजनीति करती है। ऐसे में यदि उनके समर्थकों के वोट ही सूची से बाहर हो जाएं, तो यह उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यही कारण है कि उन्होंने इस मुद्दे को इतने आक्रामक तरीके से उठाया।

उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की बजाय अव्यवस्था और अराजकता का माहौल बन गया है। उनके अनुसार, प्रदेश में अवैध कारोबार और नशे का व्यापार तेजी से बढ़ा है, जिससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो विकास कार्य हुए थे, वे आज भी उदाहरण के रूप में सामने हैं। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे अपनी सरकार की दूरदर्शिता का प्रतीक बताया।

इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की है। मणिकर्णिका घाट और अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा विरासत की दुश्मन बन चुकी है। यह बयान सीधे तौर पर भाजपा की उस राजनीति को चुनौती देता है, जिसमें वह खुद को सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों का रक्षक बताती है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अखिलेश यादव का यह बयान केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे उठाकर वे अपने समर्थकों को एकजुट करने और उन्हें मतदान के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही, यह संदेश भी देने की कोशिश है कि यदि उनके वोट काटे गए हैं, तो यह लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है।

दूसरी ओर, भाजपा और चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। यदि इन आरोपों को खारिज किया जाता है, तो यह राजनीतिक विवाद और गहरा सकता है। वहीं यदि किसी स्तर पर जांच की घोषणा होती है, तो यह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक कदम हो सकता है।

देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता है। यदि जनता को यह विश्वास हो कि उनका वोट सुरक्षित है और सही तरीके से गिना जाएगा, तभी लोकतंत्र मजबूत रह सकता है। लेकिन यदि इस विश्वास में दरार आती है, तो इसका असर केवल एक चुनाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र पर पड़ता है।

अखिलेश यादव के आरोपों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे चुनावी तंत्र में सुधार की जरूरत है? क्या मतदाता सूची की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की आवश्यकता है? क्या राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया में अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि ठोस सुधारों से ही मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं होंगे, बल्कि यह विश्वास और पारदर्शिता की भी परीक्षा होंगे। जनता किस पर भरोसा करती है और किसके आरोपों को सच मानती है, यह आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि इस मुद्दे ने चुनावी माहौल को और अधिक गरमा दिया है और राजनीतिक दलों के बीच टकराव को नई दिशा दे दी है।

बदलते बस्तर की कहानी: बंदूकों से लौटते कदम और शांति की ओर बढ़ता एक नया सवेरा

छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और वर्षों से हिंसा की छाया में जीते रहे बस्तर क्षेत्र से अब एक ऐसी खबर सामने आई है, जो केवल सुरक्षा दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है। जगदलपुर से आई इस खबर ने यह संकेत दे दिया है कि अब बस्तर धीरे-धीरे नक्सलवाद की पकड़ से बाहर निकलने की ओर अग्रसर है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब आत्मसमर्पण और मुख्यधारा में लौटने की इच्छा दिखाई दे रही है।

हाल ही में प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े 42 सशस्त्र कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह संख्या भले ही आंकड़ों में एक घटना लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश कहीं अधिक बड़ा और गहरा है। इन आत्मसमर्पण करने वालों में केवल निचले स्तर के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि संगठन के उच्च पदों पर रहे लोग भी शामिल हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने इसे नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक निर्णायक मोड़ बताया है।

यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) जैसे संगठन की सशस्त्र इकाइयों से जुड़े लोग शामिल हैं। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी लंबे समय से नक्सल आंदोलन का सबसे आक्रामक और प्रभावी हिस्सा रहा है। ऐसे में जब इसी इकाई के कमांडर स्तर के लोग हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करते हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, बल्कि यह पूरे संगठन की आंतरिक स्थिति को उजागर करता है।

बस्तर में पिछले कुछ वर्षों से लगातार सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों ने नक्सलियों के नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर किया है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा गांव-गांव तक पहुंच बनाने, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने से स्थानीय लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। पहले जहां लोग डर और मजबूरी में नक्सलियों का साथ देते थे, वहीं अब वे विकास और स्थिरता की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने भी यह स्वीकार किया है कि हिंसा का रास्ता उन्हें केवल विनाश की ओर ले जा रहा था। वर्षों तक जंगलों में छिपकर जीना, लगातार खतरे में रहना और परिवार से दूर रहना—यह सब उनके लिए अब असहनीय हो चुका था। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि सरकार उन्हें पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन का अवसर दे रही है, तो उन्होंने बंदूक छोड़ने का फैसला किया। सुंदरराज पी. ने इस मौके पर बाकी नक्सलियों से भी अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट आएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी आत्मसमर्पण करेगा, उसे सुरक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन की सुविधाएं दी जाएंगी।

यह संदेश केवल एक अपील नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पहल भी है, जिसके जरिए सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि नक्सल आंदोलन की वैचारिक जमीन अब कमजोर पड़ रही है। एक समय था जब यह आंदोलन सामाजिक अन्याय और अधिकारों की लड़ाई के रूप में देखा जाता था, लेकिन धीरे-धीरे यह हिंसा और आतंक का पर्याय बन गया। इससे आम लोगों का विश्वास इस आंदोलन से उठने लगा। अब जब विकास की योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं और लोगों को बेहतर जीवन के अवसर मिल रहे हैं, तो वे हिंसा से दूर होना ही बेहतर समझ रहे हैं।

बस्तर जैसे क्षेत्र में यह बदलाव आसान नहीं है। यहां दशकों से नक्सलवाद की जड़ें गहरी रही हैं और इसे खत्म करने के लिए केवल सैन्य कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों की भी जरूरत होती है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने इस दिशा में संतुलित रणनीति अपनाई है—एक ओर जहां सख्ती से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास का अवसर दिया जा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े सामाजिक परिवर्तन के रूप में भी देखा जा सकता है। यह केवल नक्सलियों का आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि एक मानसिक बदलाव का संकेत है। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक हिंसा के रास्ते पर चलने के बाद उसे छोड़कर शांति का रास्ता चुनता है, तो यह समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश होता है। बस्तर के लोगों के लिए यह एक नई उम्मीद की शुरुआत है। लंबे समय से हिंसा और अस्थिरता का सामना कर रहे इस क्षेत्र में अब शांति और विकास की संभावना मजबूत होती दिख रही है। यदि इसी तरह आत्मसमर्पण और पुनर्वास की प्रक्रिया जारी रहती है, तो आने वाले वर्षों में बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त हो सकता है। हालांकि, यह भी सच है कि अभी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है। जंगलों में अब भी कुछ सक्रिय नक्सली गुट मौजूद हैं, जो समय-समय पर हिंसक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इसलिए सुरक्षा बलों और प्रशासन को सतर्क रहना होगा और अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा। अंततः यह कहा जा सकता है कि बस्तर में हुआ यह आत्मसमर्पण केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दिशा है—एक ऐसा संकेत जो बताता है कि अब बंदूक की भाषा नहीं, बल्कि विकास और शांति की भाषा ज्यादा प्रभावी हो रही है।

नेपाल सीमा के साये में सिमटी मतदाता सूची: यूपी के सात जिलों में 17 लाख नाम कटने से उठे बड़े सवाल

उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हो रही है, वह है मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हुई कटौती। खासतौर पर भारत-नेपाल सीमा से सटे सात जिलों में 17 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबर ने राजनीतिक हलकों से लेकर आम जनता तक में चिंता और बहस दोनों को जन्म दे दिया है। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की उस बुनियाद से जुड़ा सवाल है, जिसमें हर नागरिक का वोट उसका अधिकार और उसकी पहचान माना जाता है।

प्रदेश के जिन सात जिलों में यह बदलाव सबसे ज्यादा देखने को मिला है, उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज शामिल हैं। इन सभी जिलों की एक खासियत यह है कि ये सीधे तौर पर नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं, जहां दशकों से 'रोटी-बेटी' का रिश्ता कायम रहा है। यही सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव अब प्रशासनिक और चुनावी प्रक्रिया के लिए एक चुनौती बनता नजर आ रहा है।

आंकड़ों के मुताबिक, इन सात जिलों में कुल 17 लाख 36 हजार 132 मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। यदि प्रतिशत के आधार पर देखा जाए, तो यह लगभग 12.80 प्रतिशत की गिरावट है, जो अपने आप में काफी बड़ी संख्या मानी जाती है। यह गिरावट ऐसे समय

में सामने आई है जब पूरे प्रदेश में औसतन 13.24 प्रतिशत मतदाता कम हुए हैं, लेकिन कुछ सीमावर्ती जिलों में यह आंकड़ा औसत से भी अधिक है। उदाहरण के तौर पर बलरामपुर में 17.20 प्रतिशत, बहराइच में 16.12 प्रतिशत और सिद्धार्थनगर में 14.32 प्रतिशत मतदाता कम हुए हैं।

संख्या के लिहाज से देखें तो बहराइच में सबसे ज्यादा 4 लाख 26 हजार 910 नाम कटे हैं, जबकि सिद्धार्थनगर में 2 लाख 81 हजार 20 और बलरामपुर में 2 लाख 72 हजार 272 मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है, जहां कटौती का प्रतिशत कम दर्ज किया गया है।

इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण है सीमा क्षेत्र में अवैध घुसपैठ की समस्या। भारत-नेपाल सीमा खुली होने के कारण लोगों का आवागमन आसान है, जिससे नागरिकता की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। प्रशासन का मानना है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए यह कदम जरूरी था, ताकि केवल वैध नागरिकों के नाम ही सूची में शामिल रहें।

लेकिन इस प्रक्रिया ने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। खासतौर पर उन महिलाओं का मुद्दा सामने आया है, जिन्होंने नेपाल से आकर भारत के सीमावर्ती जिलों में शादी की है। ये महिलाएं वर्षों से भारत में रह रही हैं, लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता के दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे में उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने पर सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी बहस छिड़ गई है। यह केवल कानूनी नहीं, बल्कि संवेदनशील सामाजिक मुद्दा भी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई मामलों में वास्तविक मतदाताओं के नाम भी सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे उन्हें अपने अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया नियमों और जांच के आधार पर की गई है और किसी भी तरह की त्रुटि को सुधारने के लिए अपील का प्रावधान मौजूद है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से यह मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर पहले ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका आरोप है कि यह केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति हो सकती है, जिसके तहत खास वर्गों के वोटरों को निशाना बनाया गया है। हालांकि सत्तारूढ़ पक्ष इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है और इसे पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया कदम बताता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि मतदाता सूची में इस तरह की बड़ी कटौती का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। सीमावर्ती जिलों में सामाजिक संरचना और जातीय समीकरण काफी जटिल होते हैं, ऐसे में लाखों वोटरों के नाम हटने से राजनीतिक संतुलन बदल सकता है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं।

इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में है। आयोग का कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करना है। इसके तहत मृत, स्थानांतरित या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाते हैं, तो पारदर्शिता और प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

डिजिटल जाल में फंसी मासूमियत: बागपत में पढ़े लिखे युवाओं का साइबर ठगी साम्राज्य बेनकाब

उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आई यह घटना केवल एक आपराधिक मामले की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते समाज, तकनीक के दुरुपयोग और युवाओं की भटकती दिशा का आईना भी है। जहां एक ओर शिक्षा को सफलता की कुंजी माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसी शिक्षा का इस्तेमाल जब अपराध के लिए होने लगे, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बन जाता है। हाल ही में बागपत पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश इसी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है।

यह गिरोह कोई साधारण अपराधी समूह नहीं था, बल्कि इसमें शामिल युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कोई बीएससी का छात्र था, तो कोई एमबीए, बीबीए या बीसीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर रहा था। यानी वे युवा, जिनसे समाज को भविष्य की उम्मीद होती है, उन्होंने ही तकनीक को धोखे का हथियार बना लिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये आरोपी बेहद संगठित तरीके से काम करते थे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों को ठगते थे।

गिरोह का तरीका बेहद चालाकी भरा था। ये लोग सर्च इंजन पर ग्रोसरी और सॉफ्ट ड्रिंक से जुड़े फर्जी विज्ञापन डालते थे, जो देखने में बिल्कुल असली लगते थे। जब कोई ग्राहक इन विज्ञापनों के जरिए संपर्क करता, तो ये खुद को दुकानदार बताकर विश्वास जीतते थे। इसके बाद ग्राहक को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहा जाता और जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता, आरोपी मोबाइल नंबर बंद कर देते और गायब हो जाते। इस पूरी प्रक्रिया में इतना प्रोफेशनलिज्म था कि आम आदमी को शक तक नहीं होता।

पुलिस के अनुसार, इस गिरोह के खिलाफ अब तक करीब 20 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं और ठगी की कुल रकम लगभग एक करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा था। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आरोपी अलग-अलग राज्यों के बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे, जिससे पैसे का ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो जाता था।

जब पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ा, तो उनके पास से जो सामान बरामद हुआ, वह भी चौंकाने वाला था। 11 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 24 सिम कार्ड, एक टैबलेट, डेबिट कार्ड, वाईफाई डिवाइस, अवैध हथियार और एक लग्जरी कार—ये सभी चीजें इस बात की गवाही देती हैं कि यह गिरोह किस स्तर पर काम कर रहा था। तकनीकी उपकरणों की इतनी बड़ी संख्या इस बात का संकेत है कि यह कोई छोटा-मोटा अपराध नहीं, बल्कि पूरी तरह से संगठित साइबर क्राइम नेटवर्क था।

लेकिन इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि आखिर पढ़े-लिखे युवा इस रास्ते पर क्यों जा रहे हैं। क्या यह केवल पैसे का लालच है, या फिर सिस्टम की कोई ऐसी खामी है, जो उन्हें गलत दिशा में धकेल रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि आज के समय में तेजी से बदलती जीवनशैली, सोशल मीडिया का प्रभाव और जल्दी अमीर बनने की चाह युवाओं को ऐसे जोखिम भरे रास्तों की ओर आकर्षित कर रही है।

इसके अलावा, बेरोजगारी और प्रतिस्पर्धा का दबाव भी एक बड़ा कारण हो सकता है। जब युवा अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वे आसान और त्वरित पैसे के रास्ते तलाशने लगते हैं। साइबर क्राइम उन्हें एक ऐसा माध्यम देता है, जहां कम समय में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है और पकड़े जाने की संभावना भी अपेक्षाकृत कम होती है—हालांकि यह सोच पूरी तरह गलत साबित हो रही है।

इस घटना ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है—क्या हमारी शिक्षा प्रणाली केवल डिग्री देने तक सीमित हो गई है? क्या हम अपने युवाओं को नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारियों की शिक्षा देने में पीछे रह गए हैं? यदि शिक्षा केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित रह जाए और उसमें नैतिकता का अभाव हो, तो उसका परिणाम इसी तरह के मामलों में सामने आता है।

पुलिस की कार्रवाई ने यह जरूर साबित किया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कोई भी अपराधी ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि समाज और प्रशासन मिलकर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाएं। लोगों को यह समझना होगा कि ऑनलाइन किसी भी विज्ञापन या ऑफर पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है।

डिजिटल युग में जहां एक क्लिक पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं एक छोटी सी लापरवाही भारी नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोग सतर्क रहें, किसी भी अनजान नंबर या वेबसाइट पर भुगतान करने से पहले उसकी सत्यता जांचें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। बागपत की यह घटना केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com* navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

दीदी की रसोई: सस्ती थाली से सशक्तिकरण तक बिहार में महिलाओं की नई आर्थिक क्रांति का मॉडल

पटना से उठी एक शांत लेकिन दूरगामी प्रभाव वाली पहल आज पूरे बिहार के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को बदलने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रही है। 'दीदी की रसोई' केवल सस्ती थाली उपलब्ध कराने की योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने, सामाजिक सम्मान हासिल करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का एक व्यापक आंदोलन बन चुकी है। जिस समय देश के कई हिस्सों में महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दे आमजन के लिए चुनौती बने हुए हैं, उस समय यह योजना एक ऐसे समाधान के रूप में सामने आई है, जिसमें सेवा, संवेदना और स्वावलंबन तीनों का संतुलित संगम देखने को मिलता है।

इस पहल की खास बात यह है कि इसे किसी बड़े कॉरपोरेट ढांचे या निजी संस्थान ने नहीं, बल्कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी साधारण ग्रामीण और शहरी महिलाओं ने अपने श्रम और संकल्प के बल पर खड़ा किया है। जीविका समूह के माध्यम से संचालित यह योजना अब लाखों महिलाओं के जीवन में स्थायी बदलाव ला रही है। शुरुआत में इसे सीमित स्तर पर शुरू किया गया था, लेकिन जैसे-जैसे लोगों ने इसकी गुणवत्ता, स्वच्छता और किफायती दरों को अनुभव किया, इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती चली गई।

हाल ही में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय परिसर में 'अन्नपूर्णा जीविका दीदी की रसोई' का उद्घाटन इस योजना के विस्तार का एक महत्वपूर्ण संकेत है। विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थान में इस तरह की रसोई का संचालन केवल भोजन की सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों और कर्मचारियों को सामाजिक भागीदारी और स्थानीय संसाधनों के महत्व को समझने का अवसर भी देता है। यहां लगभग 500 से अधिक छात्र-छात्राओं और स्टाफ को प्रतिदिन सस्ते दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे न केवल उनकी जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार, यह योजना अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां इसे बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों तक विस्तारित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि 18 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस पहल को केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में देख रही है।

इस योजना की जड़ें उस सोच में हैं, जहां महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि परिवर्तन का वाहक माना गया है। जीविका के तहत अब तक 11 लाख 67 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं, जिनसे 1 करोड़ 50 लाख से अधिक परिवार जुड़े हैं। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं, बल्कि उस विश्वास और सामूहिक शक्ति का प्रतीक हैं, जिसने बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।

'दीदी की रसोई' में काम करने वाली महिलाएं केवल खाना बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे पूरी प्रक्रिया की प्रबंधक भी हैं—खरीदारी से लेकर वितरण तक, गुणवत्ता नियंत्रण से लेकर ग्राहक संतुष्टि तक, हर स्तर पर उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। इससे उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित हो रही है और वे आत्मविश्वास के साथ अपने निर्णय लेने में सक्षम बन रही हैं।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी पारदर्शिता और गुणवत्ता है। खाने की कीमतें इस तरह निर्धारित की गई हैं कि आम आदमी आसानी से इसे वहन कर सके, वहीं गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाता। यही कारण है कि यह रसोई धीरे-धीरे एक भरोसेमंद ब्रांड बनती जा रही है। कई स्थानों पर तो लोग निजी होटल और ढाबों की बजाय 'दीदी की रसोई' को प्राथमिकता देने लगे हैं।

सामाजिक दृष्टि से भी इस पहल का प्रभाव व्यापक है। जहां एक ओर यह महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दे रही है, वहीं दूसरी ओर समाज में उनकी भूमिका को भी पुनर्परिभाषित कर रही है। अब वे केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं और अपने परिवार के साथ-साथ समाज के विकास में भी योगदान दे रही हैं।

सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता—पहले चरण में 10 हजार रुपये और दूसरे चरण में 20 हजार रुपये—महिलाओं को अपने व्यवसाय को शुरू करने और विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह सहायता केवल वित्तीय समर्थन नहीं, बल्कि एक विश्वास का प्रतीक है कि महिलाएं यदि अवसर और संसाधन मिलें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं।

आने वाले समय में 'दीदी की रसोई' का विस्तार जिस गति से प्रस्तावित है, वह इसे एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित कर सकता है। यदि अन्य राज्य भी इस पहल को अपनाते हैं, तो यह देशभर में महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है।

अंततः, 'दीदी की रसोई' केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक विचार है—एक ऐसा विचार जो यह साबित करता है कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह पहल न केवल भूख को मिटाने का काम कर रही है, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास की एक नई कहानी भी लिख रही है, जिसमें हर 'दीदी' अपने संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक मिसाल बनती जा रही है।

पटना में साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई: बच्चों के अश्लील कंटेंट शेयर करने वाला आरोपी गिरफ्तार, नेटवर्क की जांच तेज

पटना। बिहार की राजधानी पटना में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को शेयर और अपलोड करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह मामला न केवल कानून व्यवस्था बल्कि समाजिक सुरक्षा और नैतिकता के लिहाज से भी बेहद गंभीर माना जा रहा है।

साइबर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पालीगंज थाना क्षेत्र का निवासी एक युवक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो साझा कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया और तकनीकी निगरानी के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ और डिजिटल जांच के बाद उसकी संलिप्तता की पुष्टि होने पर उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त किया, जिसमें बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक कंटेंट मिला। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सोशल मैसेजिंग ऐप Telegram पर काफी सक्रिय था और कई संदिग्ध चैनलों से जुड़ा हुआ था। वह इन चैनलों के माध्यम से बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री को डाउनलोड कर आगे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर शेयर और अपलोड करता था।

साइबर थाना के डीएसपी नीतिश चंद्र धारिया के अनुसार, बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट का निर्माण, संग्रहण और प्रसारण—तीनों ही गंभीर आपराधिक कृत्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी का नेटवर्क कितना व्यापक है और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। जांच एजेंसियों को आरोपी के डिवाइस से वर्ष 2023 से जुड़ी गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि वह पिछले तीन-चार वर्षों से इस अवैध गतिविधि में लिप्त था। फिलहाल पुलिस यह भी खंगाल रही है कि क्या आरोपी का संबंध किसी बड़े अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से है। अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके पास इस तरह का कोई भी कंटेंट आता है तो उसे तुरंत डिलीट करें और इसकी सूचना संबंधित एजेंसियों को दें। ऐसे कंटेंट को फॉरवर्ड करना भी कानूनन अपराध है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। यह मामला एक बार फिर इस बात को उजागर करता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग किस तरह समाज के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे में जागरूकता, सतर्कता और कानून का सख्त पालन ही इस तरह के अपराधों पर रोक लगाने का सबसे प्रभावी उपाय है।

यूपी में रोजगार का बड़ा अवसर: मुजफ्फरनगर में 'रोजगार महाकुंभ' आज से, 25 हजार नौकरियों का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के नुमाइश ग्राउंड में 13 अप्रैल से शुरू हो रहा 'रोजगार महाकुंभ' केवल एक भर्ती मेला नहीं, बल्कि बदलते भारत की उस सोच का प्रतीक है, जिसमें युवा शक्ति को विकास का सबसे बड़ा इंजन माना जा रहा है। इस विशाल आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जो स्वयं इस कार्यक्रम में युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उनके सपनों को नई दिशा देंगे।

इस रोजगार महाकुंभ की सबसे बड़ी खासियत इसकी व्यापकता और विविधता है। यहां 200 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में 25,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। यह आयोजन इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इसमें छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी सीधे बड़े उद्योगों और कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलेगा। यह पहल उस अंतर को पाटने का प्रयास है, जो अक्सर बड़े शहरों और छोटे कस्बों के बीच रोजगार के अवसरों को लेकर देखने को मिलता है।

कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी और प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की उपस्थिति इस बात को और मजबूती देती है कि सरकार रोजगार और कौशल विकास को लेकर गंभीर है। उनके अनुसार, इस तरह के रोजगार मेले न केवल नौकरी दिलाने का माध्यम हैं, बल्कि युवाओं को उनके कौशल के अनुसार सही दिशा देने का भी कार्य करते हैं।

इस महाकुंभ में शामिल होने वाली कंपनियां विभिन्न सेक्टर से जुड़ी हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी-आईटीईएस, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और परिधान उद्योग प्रमुख हैं। Tata Motors, Paytm, JBM Group, Zepto और L&T Finance जैसी कंपनियों की भागीदारी इस आयोजन को और भी आकर्षक बनाती है। इन कंपनियों के प्रतिनिधि सीधे उम्मीदवारों से मिलेंगे, इंटरव्यू लेंगे और योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगे।

इस रोजगार मेले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें भाग लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता की सीमा बहुत व्यापक रखी गई है। 8वीं पास से लेकर आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्नातक, बीटेक और एमबीए तक के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि समाज के हर वर्ग के युवा इस अवसर का लाभ उठा सकें। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है, जिससे अनुभवी और नए दोनों तरह के उम्मीदवारों को मौका मिल सके।

सरकार की ओर से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो। चयनित अभ्यर्थियों को उसी दिन लेटर ऑफ इंटेंट (LOI), ऑफर लेटर या जॉइनिंग लेटर प्रदान किए जाएंगे। यह कदम युवाओं में विश्वास पैदा करता है और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाता है। साथ ही, यह उन युवाओं के लिए भी राहत की बात है, जो लंबे समय तक नौकरी के इंतजार में रहते हैं। कौशल विकास मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और आईटीआई से प्रशिक्षित युवाओं को इस मेले में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि जो युवा पहले से ही किसी कौशल में प्रशिक्षित हैं, उन्हें तुरंत रोजगार से जोड़ा जा सके। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

यह रोजगार महाकुंभ केवल नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत का संकेत भी है। जब युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार मिलता है, तो वे आत्मनिर्भर बनते हैं, उनके परिवारों की स्थिति सुधरती है और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। यही कारण है कि ऐसे आयोजनों को 'महाकुंभ' का नाम दिया गया है, क्योंकि यहां केवल रोजगार नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण होता है।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां युवा आबादी का प्रतिशत काफी अधिक है, इस तरह के रोजगार मेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह पहल राज्य सरकार की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जा रही है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले समय में यदि इस तरह के रोजगार महाकुंभ नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, तो यह न केवल बेरोजगारी दर को कम करने में मदद करेंगे, बल्कि प्रदेश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएंगे। यह आयोजन एक उम्मीद है, एक अवसर है और एक नई शुरुआत है—जहां हर युवा अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकता है।

जेल की दीवारों के भीतर रची गई करोड़ों की साजिश, दरभंगा लूट कांड का सनसनीखेज खुलासा

दरभंगा। बिहार के दरभंगा में हुए बहुचर्चित सोना-चांदी लूट कांड ने जिस तरह पूरे इलाके को दहला दिया था, उसी तरह अब इस मामले का खुलासा भी उतना ही चौंकाने वाला साबित हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि करीब 2 करोड़ रुपये की इस बड़ी वारदात की साजिश जेल की चारदीवारी के भीतर बैठकर रची गई थी। यह तथ्य न केवल अपराध की गंभीरता को उजागर करता है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े करता है।

3 अप्रैल 2026 को दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स में हुई इस लूट ने स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया था। दिनदहाड़े हुई इस घटना में अपराधियों ने दुकान से करीब 700 ग्राम सोना, 20 से 25 किलो चांदी और लगभग 10 लाख रुपये नकद लूट लिए थे। वारदात को जिस सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, उससे यह साफ हो गया था कि इसके पीछे एक बड़ा और संगठित गिरोह काम कर रहा है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस ने अब इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि इस लूट की पूरी साजिश दलसिंहसराय जेल में बंद कुख्यात अपराधी भोला सिंह ने रची थी। जेल के भीतर से ही उसने अपने नेटवर्क के जरिए बाहर मौजूद साथियों को निर्देश दिए और पूरी योजना को अंजाम तक पहुंचाया।

जांच एजेंसियों के अनुसार, इस वारदात में दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय जिलों के करीब 20 अपराधी शामिल थे। इन लोगों ने पहले इलाके की रेकी की, फिर समय और परिस्थिति का आंकलन कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में 'लाइनर' की भूमिका बेहद अहम थी, जो मौके की जानकारी और गतिविधियों की निगरानी करते थे। इसी कड़ी में लहेरियासराय थाना क्षेत्र से ऋषिकेश सोनी और अभिषेक कुमार उर्फ सोनी को गिरफ्तार किया गया, जो इस वारदात के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटा रहे थे।

इसके अलावा, लूट के सामान को छिपाने के आरोप में बेगूसराय की उषा देवी को भी गिरफ्तार किया गया है। यह पहलू इस बात की ओर इशारा करता है कि गिरोह ने अपने नेटवर्क को बेहद सावधानी से तैयार किया था, जिसमें अलग-अलग भूमिकाओं के लिए अलग-अलग लोगों को शामिल किया गया था।

इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि अब तक पुलिस ने 156.44 ग्राम सोना और 8.630 किलोग्राम चांदी बरामद कर ली है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 44 लाख रुपये है। हालांकि लूटी गई नकदी अभी तक बरामद नहीं हो सकी है, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि उसे तेजी से ठिकाने लगा दिया गया।

पुलिस की इस सफलता के पीछे कई राज्यों की एजेंसियों का समन्वय भी महत्वपूर्ण रहा। बिहार एसटीएफ, उत्तर प्रदेश एसटीएफ, असम पुलिस और दरभंगा एसआईटी की संयुक्त टीम ने मिलकर आरोपियों का पीछा किया और उन्हें अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। घटना के बाद आरोपी विभिन्न राज्यों में भाग गए थे, जिससे उनकी गिरफ्तारी चुनौतीपूर्ण बन गई थी। लेकिन तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल और स्थानीय इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने धीरे-धीरे पूरे नेटवर्क को ट्रैक किया।

गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो पिस्तौल, नौ जिंदा गोलियां, चार मोटरसाइकिल और आठ मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। ये सभी साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि गिरोह पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम देने निकला था और उनके पास भागने तथा संपर्क बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद थे।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जेल के भीतर बैठकर इतने बड़े अपराध की साजिश कैसे रची जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जेलों में मोबाइल फोन और संचार के अन्य अवैध साधनों की उपलब्धता अपराधियों को बाहरी दुनिया से जुड़े रहने का मौका देती है, जिसका वे दुरुपयोग करते हैं। इस मामले ने जेल प्रशासन की सतर्कता और निगरानी व्यवस्था की खामियों को भी उजागर किया है।

फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही पूरे गिरोह को पकड़ लिया जाएगा और इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर संतोष जताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग भी की है।

दरभंगा लूट कांड का यह खुलासा केवल एक आपराधिक घटना का समाधान नहीं है, बल्कि यह उस जटिल अपराध तंत्र की झलक भी दिखाता है, जो आज के दौर में तकनीक और नेटवर्क के सहारे संचालित हो रहा है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को और अधिक सतर्क, तकनीकी रूप से सक्षम और समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

लखनऊ और गुजरात के बीच होगी रणनीति, संयम और ताकत की असली परीक्षा

लखनऊ। इंडियन प्रीमियर लीग का रोमांच अपने चरम पर है और इसी कड़ी में रविवार को इकाना स्टेडियम एक ऐसे मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है, जिसमें सिर्फ दो टीमें नहीं बल्कि दो अलग-अलग रणनीतियां, दो सोच और दो संतुलित क्रिकेट दर्शन आमने-सामने होंगे। Lucknow Super Giants और Gujarat Titans के बीच होने वाला यह मुकाबला केवल अंक तालिका की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस दबदबे की जंग भी है जो आने वाले मैचों की दिशा तय कर सकती है। घरेलू मैदान पर उतर रही लखनऊ की टीम इस मुकाबले को अपने लिए टर्निंग प्वाइंट बनाना चाहती है। शुरुआती झटकों के बाद टीम ने जिस तरह वापसी की है, उसने यह साबित कर दिया है कि उसमें दबाव से उबरने की क्षमता है। सहायक कोच लांस क्लूजनर का आत्मविश्वास भी इसी ओर इशारा करता है। उनका मानना है कि इस बार टीम की गेंदबाजी इकाई पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और घातक नजर आ रही है। तेज गेंदबाजों की धार और स्पिनरों की सटीकता ने टीम को एक ऐसा हथियार दिया है, जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तोड़ सकता है।

लखनऊ के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि उसके बल्लेबाज धीरे-धीरे लय में लौट रहे हैं। ऋषभ पंत की आक्रामकता, युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा और मध्यक्रम की स्थिरता टीम को मजबूती दे रही है। वहीं निकोलस पूरन, एडेन मार्करम और मिचेल मार्श जैसे बड़े नाम अभी पूरी तरह फॉर्म में नहीं आए हैं, लेकिन टीम प्रबंधन को भरोसा है कि ये खिलाड़ी बड़े मंच पर अपनी असली ताकत दिखाएंगे। क्लूजनर ने इन्हें "सोए हुए शेर" बताते हुए संकेत दिया कि जब ये जागेंगे, तो मैच का रुख पलट सकता है।

दूसरी ओर गुजरात की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। पिछले मुकाबले में मिली रोमांचक जीत ने टीम का मनोबल और ऊंचा कर दिया है। सहायक कोच विजय दहिया ने स्पष्ट किया है कि उनकी टीम हर परिस्थिति के लिए तैयार है और किसी भी विरोधी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें "क्रिकेट का ब्रिलिएंट स्टूडेंट" बताया, जो खेल को समझने और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में माहिर हैं।

गुजरात की सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलन है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में विविधता और फील्डिंग में चुस्ती—ये तीनों पहलू टीम को बेहद खतरनाक बनाते हैं। खासकर राशिद खान जैसे विश्वस्तरीय स्पिनर की मौजूदगी किसी भी पिच पर मैच का पासा पलट सकती है। उनके अनुभव और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता गुजरात को अतिरिक्त बढ़त देती है।

इकाना स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाने वाली है। मिक्स्ड सॉइल की इस सतह पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिल सकती है, जबकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनरों का असर बढ़ने की संभावना है। दिन के मुकाबले में ओस का प्रभाव कम रहेगा, जिससे दोनों टीमों को अपनी रणनीति स्पष्ट रूप से लागू करने का मौका मिलेगा। यही कारण है कि यह मैच केवल खिलाड़ियों की क्षमता ही नहीं, बल्कि कप्तानों की रणनीतिक सोच की भी परीक्षा लेने वाला है।

लखनऊ के लिए चुनौती यह होगी कि वह गुजरात की मजबूत शुरुआत को रोक सके। यदि पावरप्ले में विकेट निकालने में सफलता मिलती है, तो मैच पर पकड़ मजबूत हो सकती है। वहीं गुजरात की कोशिश होगी कि वह लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ संयम से खेलते हुए बड़े स्कोर की नींव रखे। दोनों टीमों के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं, इसलिए हर ओवर में रोमांच की उम्मीद की जा रही है।

इस मुकाबले की खास बात यह भी है कि दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा अब व्यक्तिगत प्रदर्शन से आगे बढ़कर सामूहिक रणनीति की लड़ाई बन चुकी है। जहां लखनऊ अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी, वहीं गुजरात अपनी निरंतरता और संतुलन के दम पर जीत की लय बनाए रखने उतरेगी।

क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला किसी उत्सव से कम नहीं होगा। स्टेडियम में दर्शकों की गूंज, खिलाड़ियों का जोश और हर गेंद पर बदलता समीकरण—यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएगा, जो आईपीएल की असली पहचान है। जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी, तो यह केवल एक मैच नहीं बल्कि एक ऐसी जंग होगी, जिसमें हर रन, हर विकेट और हर फैसला मायने रखेगा।

इकाना की इस भिड़ंत में कौन बाजी मारेगा, यह तो मैच खत्म होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि यह मुकाबला लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

थारू समाज को न्याय और अधिकार का भरोसा पलिया से उठी बदलाव की गूंज, योगी का बड़ा ऐलान

लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में आयोजित एक विशाल जनसभा उस समय ऐतिहासिक क्षण में बदल गई, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थारू जनजाति के अधिकार, सम्मान और न्याय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि वर्षों से उपेक्षा और संघर्ष झेल रहे एक समुदाय के लिए उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का संदेश बनकर उभरा। मंच से मुख्यमंत्री के शब्दों में केवल राजनीतिक संकल्प नहीं, बल्कि उस पीड़ा की स्वीकारोक्ति भी झलक रही थी, जिसे थारू समाज लंबे समय से महसूस करता आ रहा था।

सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा और संवेदनशील ऐलान करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय थारू समुदाय के लोगों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन्हें अब वापस लिया जाएगा। यह घोषणा जैसे ही लोगों तक पहुंची, पूरे मैदान में तालियों की गूंज उठी। यह केवल कानूनी राहत नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान की पुनर्स्थापना का संकेत था। वर्षों तक जिन मामलों ने इस समुदाय को मानसिक और सामाजिक दबाव में रखा, अब उनसे मुक्ति की राह खुलती नजर आ रही है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, जबकि मेहनतकश और जनजातीय समाजों को उत्पीड़न झेलना पड़ता था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब राज्य में कानून का राज स्थापित है, जहां किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अपराध और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे वह कोई भी हो।

कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू वह था, जब मुख्यमंत्री ने 6706 परिवारों को भौमिक अधिकार पत्र वितरित किए। इनमें 2350 परिवार नदी कटान से प्रभावित थे, जबकि 4356 परिवार थारू जनजाति से जुड़े थे। यह क्षण उन परिवारों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, जो पीढ़ियों से जमीन पर रहते हुए भी उसके मालिकाना हक से वंचित थे। अब उन्हें न केवल कानूनी अधिकार मिला है, बल्कि उनके भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सामाजिक असमानता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

अब वर्तमान सरकार ने इसे जमीनी स्तर पर लागू कर दिखाया है। यह बयान न केवल अतीत की कमियों को उजागर करता है, बल्कि वर्तमान की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 817 करोड़ रुपये की लागत से 314 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, सिंचाई व्यवस्था, बुनियादी ढांचे का विकास और अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। पलिया, श्रीनगर, निघासन और गोला गोकर्णनाथ जैसे क्षेत्रों में इन परियोजनाओं से विकास की नई धारा बहने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के लिए यह केवल आंकड़े नहीं, बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार की संभावनाएं हैं।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घरों की चाबियां सौंपी गईं, आंगनवाड़ी भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, और 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और नाबार्ड से जुड़ी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सहायता दी गई। यह सब मिलकर एक ऐसे समग्र विकास मॉडल की तस्वीर पेश करता है, जिसमें हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्यक्रम का सांस्कृतिक पहलू भी उतना ही आकर्षक और भावनात्मक था। थारू जनजाति के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक नृत्य और लोकगीतों ने वहां उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि थारू समाज अपनी परंपराओं और विरासत को जिस तरह संजोकर रखे हुए है, वह पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाता है। यह बयान इस बात का प्रतीक था कि विकास केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब जनजातीय और वंचित समाजों को मुख्यधारा में लाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। थारू समुदाय, जो लंबे समय तक उपेक्षा और संघर्ष का प्रतीक रहा, अब विकास और सम्मान की नई कहानी लिखने की ओर बढ़ रहा है।

अंततः, पलिया की यह सभा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन गई है। मुख्यमंत्री के ऐलान, विकास परियोजनाओं की शुरुआत और अधिकारों की बहाली—इन सबने मिलकर एक ऐसा संदेश दिया है, जो आने वाले समय में न केवल थारू समाज, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन घोषणाओं का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है और किस तरह यह बदलाव स्थायी रूप लेता है।

नकली सोने का जाल, बैंकिंग सिस्टम पर सवालः प्रयागराज में 57 लाख के गोल्ड लोन घोटाले से मचा हड़कंप

प्रयागराज के व्यस्त और प्रतिष्ठित इलाके सिविल लाइंस में स्थित केनरा बैंक की एक शाखा में सामने आया गोल्ड लोन घोटाला न केवल बैंकिंग व्यवस्था की सतर्कता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस तरह संगठित तरीके से वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक ओर जहां आम जनता अपनी जमा-पूंजी को सुरक्षित मानकर बैंकों पर भरोसा करती है, वहीं इस तरह की घटनाएं उस विश्वास को झकझोरने का काम करती हैं।

यह मामला तब उजागर हुआ, जब बैंक की नियमित ऑडिट प्रक्रिया के दौरान कुछ गोल्ड लोन खातों में संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं। शुरुआत में यह केवल एक सामान्य अनियमितता प्रतीत हुई, लेकिन जब गहराई से जांच की गई, तो मामला एक बड़े फर्जीवाड़े के रूप में सामने आया। कुल 18 खातों की जांच में पाया गया कि 16 मामलों में आरोपियों ने असली सोने की जगह नकली आभूषण गिरवी रखकर बैंक से 57 लाख 19 हजार 800 रुपये का लोन हासिल कर लिया। समय के साथ ब्याज और अन्य शुल्क जुड़ने पर यह राशि बढ़कर लगभग 64 लाख रुपये से अधिक हो गई।

यह आंकड़ा केवल एक शाखा का है, लेकिन इससे यह आशंका और गहरी हो जाती है कि कहीं इसी तरह का नेटवर्क अन्य शाखाओं और जिलों में भी सक्रिय तो नहीं। बैंकिंग क्षेत्र में गोल्ड लोन को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें गिरवी रखा गया सोना लोन की सुरक्षा के रूप में काम करता है। लेकिन जब यही सोना नकली निकल जाए, तो पूरी व्यवस्था की नींव ही हिल जाती है।

इस मामले में सबसे अहम भूमिका गोल्ड अप्रेजर की होती है, जो जमा किए गए आभूषणों की शुद्धता और मूल्य का आकलन करता है। जांच में सामने आया है कि गोल्ड अप्रेजर विष्णु शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर इन लोन को मंजूरी दी गई थी। यहीं से सवाल उठता है कि क्या यह केवल लापरवाही थी या फिर किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा? क्योंकि बैंक के नियमों के अनुसार, हर तीन महीने में किसी दूसरे अप्रेजर से पुनः जांच कराना अनिवार्य होता है। इसी प्रक्रिया के दौरान जब दोबारा मूल्यांकन किया गया, तब इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ।

बैंक प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शाखा के सहायक महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रमुख पंकज वर्मा की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर 10 अप्रैल 2026 को मामला दर्ज किया गया। हालांकि यह भी सामने आया है कि इस संबंध में प्रारंभिक शिकायत जुलाई 2025 में ही दी गई थी, जिससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई।

पुलिस अब इस मामले को एक संगठित अपराध के रूप में देख रही है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि यह काम किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरे गिरोह का हो सकता है, जो सुनियोजित तरीके से बैंकिंग प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठा रहा था। ऐसे गिरोह आमतौर पर फर्जी दस्तावेज, नकली पहचान और तकनीकी खामियों का इस्तेमाल कर बैंक से पैसा निकालते हैं और फिर उसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।

इस घटना ने बैंकिंग सेक्टर में जोखिम प्रबंधन और निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ऑडिट प्रक्रिया पर्याप्त मजबूत है? क्या अप्रेजल सिस्टम में सुधार की जरूरत है? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या इस तरह के मामलों को रोकने के लिए तकनीकी और मानवीय दोनों स्तरों पर बदलाव जरूरी है?

आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह केवल एक बैंक का नुकसान नहीं है, बल्कि यह पूरे वित्तीय तंत्र के लिए एक चेतावनी है। यदि ऐसे मामलों पर समय रहते सख्ती नहीं बरती गई, तो यह प्रवृत्ति और बढ़ सकती है, जिससे आम लोगों का बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा कमजोर पड़ सकता है।

सामाजिक स्तर पर भी इसका प्रभाव कम नहीं है। जब आम नागरिक यह सुनते हैं कि नकली सोना रखकर लाखों रुपये का लोन लिया जा सकता है, तो यह न केवल व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि ईमानदार ग्राहकों के लिए भी असहज स्थिति पैदा करता है। इससे बैंकिंग प्रक्रिया और अधिक जटिल और सख्त हो सकती है, जिसका असर अंततः आम जनता पर ही पड़ेगा।

फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य जुटा रही है। कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। बैंक प्रबंधन भी आंतरिक स्तर पर अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

अंततः, प्रयागराज का यह गोल्ड लोन घोटाला केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि एक संकेत है—एक चेतावनी कि तकनीकी प्रगति और वित्तीय विस्तार के इस दौर में सुरक्षा और सतर्कता को और मजबूत करने की जरूरत है। अब यह देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले को किस हद तक सुलझा पाती हैं और क्या इस घटना से सबक लेकर बैंकिंग प्रणाली को और सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

सुरक्षित निवेश की दौड़ में सोना रिकॉर्ड पर, डेढ़ लाख के पार पहुंचकर बाजार में मचाई हलचल

नई दिल्ली। वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक उतार-चढ़ाव के दौर में जब निवेशक अपने पूंजी की सुरक्षा को लेकर सबसे अधिक सतर्क हो जाते हैं, तब सोना एक बार फिर भरोसे का सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता, मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव के बीच निवेशकों ने सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख किया है, जिसका सीधा फायदा सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं को मिला है। यही वजह है कि इस सप्ताह सोने ने न केवल नई ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि भारतीय बाजार में डेढ़ लाख रुपये प्रति दस ग्राम के ऐतिहासिक स्तर को पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया।

कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन Multi Commodity Exchange (MCX) पर सोने के जून वायदा भाव में करीब 1.65 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई और यह 1,52,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गया। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बाजार की उस मानसिकता का संकेत है, जिसमें निवेशक जोखिम से बचने के लिए तेजी से सोने की ओर झुक रहे हैं। इसी के साथ चांदी ने भी अपनी चमक बरकरार रखते हुए मई वायदा में 2,43,300 रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर छू लिया, जो हाल के उच्चतम स्तरों में गिना जा रहा है।

घरेलू सर्राफा बाजार में भी यही रुझान साफ तौर पर नजर आया। India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, 999 शुद्धता वाला सोना सप्ताह की शुरुआत में 1,47,891 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो सप्ताह के अंत तक बढ़कर 1,50,327 रुपये तक पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत भी इस दौरान लगभग 9 हजार रुपये बढ़कर 2,39,934 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। यह तेजी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बाजार में सुरक्षित निवेश की मांग लगातार मजबूत हो रही है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की चमक कम नहीं हुई है। COMEX पर सोने की कीमत साप्ताहिक आधार पर लगभग 3 प्रतिशत उछलकर 4,787.40 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर बंद हुई। विश्लेषकों का मानना है कि 5,000 डॉलर प्रति औंस का स्तर अब एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बाधा बन चुका है। यदि यह स्तर पार होता है, तो सोने में और तेज उछाल देखने को मिल सकता है, जो वैश्विक बाजारों के साथ-साथ भारतीय कीमतों को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है।

इस तेजी के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव है, जिसने निवेशकों को जोखिम भरे निवेश से दूर रहने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा, डॉलर की चाल, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका भी सोने को मजबूत आधार दे रही है। जब भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सोने को "सेफ हेवन" यानी सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखते हैं, और यही प्रवृत्ति इस समय भी देखने को मिल रही है।

तकनीकी विश्लेषण के लिहाज से भी सोने की स्थिति मजबूत बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, MCX पर 1,48,000 से 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर मजबूत सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रहा है। यानी यदि कीमतों में गिरावट भी आती है, तो इस दायरे में खरीदारी बढ़ सकती है। वहीं ऊपर की ओर 1,54,000 से 1,55,000 रुपये का स्तर अगला बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है, जिसे पार करने पर बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है।

चांदी के मामले में भी स्थिति कुछ इसी तरह की है। 2,30,000 से 2,25,000 रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर मजबूत सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है, जबकि बड़ी गिरावट की स्थिति में 2,05,000 से 2,00,000 रुपये के बीच मजबूत आधार मिलने की संभावना है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए गिरावट की संभावना कम और स्थिर या बढ़ती कीमतों की संभावना अधिक मानी जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों की दिशा काफी हद तक वैश्विक घटनाक्रम पर निर्भर करेगी। यदि अंतरराष्ट्रीय तनाव बना रहता है और आर्थिक अनिश्चितता जारी रहती है, तो सोने में निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ सकती है। वहीं यदि हालात सामान्य होते हैं, तो कीमतों में कुछ स्थिरता आ सकती है।

फिलहाल, बाजार का रुख साफ है—निवेशक सुरक्षा चाहते हैं, और सोना उन्हें वही सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यही वजह है कि डेढ़ लाख रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद भी सोने की चमक फीकी पड़ने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। बल्कि, यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक वैश्विक अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक सोना निवेशकों के पोर्टफोलियो का सबसे मजबूत स्तंभ बना रहेगा।

पंकज शुक्ला हत्याकांड में पुलिस की बड़ी सफलता, मुठभेड़ के बाद दो इनामी बदमाश गिरफ्तार

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चर्चित पंकज शुक्ला हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे दो इनामी बदमाशों को विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान हुई कार्रवाई में एक आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश सकुशल पकड़ा गया। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने शनिवार को पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि एसटीएफ टीम ने हत्या के मुख्य आरोपितों विवेक पाण्डेय उर्फ ऋषिक और विपिन त्रिपाठी को पकड़कर अंतू थाना पुलिस के सुपुर्द किया था। दोनों आरोपित पंकज शुक्ला की हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहे थे और उनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की कई टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थीं, जिसके बाद आखिरकार यह सफलता हाथ लगी।

घटना का नाटकीय मोड़ तब आया, जब पुलिस टीम आरोपितों को हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए बैजलपुर पुल के पास लेकर पहुंची। इसी दौरान विवेक पाण्डेय ने अचानक मौका देखकर पुलिसकर्मियों को धक्का दिया और अपने पास छिपाए अवैध तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। इस अचानक हमले से कुछ क्षणों के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस टीम ने संयम और सतर्कता दिखाते हुए तत्काल जवाबी कार्रवाई की।

आत्मरक्षा में की गई इस जवाबी फायरिंग में विवेक पाण्डेय के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने बिना समय गंवाए उसे तत्काल जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ भेजा, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं दूसरे आरोपी विपिन त्रिपाठी को पुलिस ने सुरक्षित हिरासत में ले लिया।

पुलिस के अनुसार, आरोपितों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और तीन खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। बरामद हथियारों और अन्य साक्ष्यों को जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है, ताकि मामले की कड़ियों को और मजबूत किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से न केवल हत्या के इस मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, बल्कि जिले में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क पर भी बड़ा असर पड़ेगा।

पंकज शुक्ला हत्याकांड के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। पुलिस पर भी इस मामले को जल्द सुलझाने का दबाव था। ऐसे में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि कानून से बचकर भागना आसान नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपितों से पूछताछ के दौरान इस हत्याकांड के पीछे की पूरी साजिश और अन्य संभावित सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को पुलिस की अपराध नियंत्रण नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा और मजबूत होगा।

स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। उनका कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी से इलाके में शांति और सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। वहीं पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

कुल मिलाकर, यह मुठभेड़ और गिरफ्तारी न केवल एक चर्चित हत्याकांड के खुलासे की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे पूरे घटनाक्रम की परतें और साफ हो सकेंगी।

युद्ध की मार से जूझता बीयर उद्योग, लागत के दबाव में कराहती कंपनियां और राहत की आस में टिकी निगाहें

नई दिल्ली। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव जब बढ़ता है तो उसका असर केवल सीमाओं और कूटनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और उद्योगों को भी गहराई से प्रभावित करता है। इन दिनों मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाएं किस तरह घरेलू बाजारों की दिशा और दशा बदल सकती हैं। भारत का बीयर उद्योग भी इस उथल-पुथल से अछूता नहीं रहा है। बढ़ती लागत, कच्चे माल की कमी और सप्लाई चेन में आ रही रुकावटों ने इस उद्योग को एक कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां से बाहर निकलने के लिए कंपनियां सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की उम्मीद लगाए बैठी हैं।

देश के शराब उद्योग का एक बड़ा हिस्सा बीयर बाजार पर आधारित है, जिसका आकार लगभग 65 अरब डॉलर का माना जाता है। यह उद्योग न केवल हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है, बल्कि सरकार के राजस्व का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन वर्तमान हालात में यह उद्योग तीन तरफा दबाव में फंसा हुआ है—एक ओर कच्चे माल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी ओर सप्लाई चेन बाधित हो रही है, और तीसरी ओर नियामकीय सीमाएं कंपनियों के हाथ बांध रही हैं।

मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और परिवहन लागत में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर पैकेजिंग सामग्री पर पड़ा है। बीयर उद्योग के लिए ग्लास बोतलें और एल्यूमीनियम कैन सबसे जरूरी घटक होते हैं, लेकिन इनकी उपलब्धता अब चुनौती बनती जा रही है। घरेलू स्तर पर इनका उत्पादन पहले से ही सीमित था, और अब मांग बढ़ने के कारण यह कमी और अधिक गहरी हो गई है। स्थानीय निर्माता अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं, फिर भी वे बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

इस संकट को देखते हुए Federation of European Business in India ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर ग्लास बोतलों और एल्यूमीनियम कैन पर लगने वाली 10 प्रतिशत आयात शुल्क को अस्थायी रूप से हटाने की मांग की है। इस संगठन में Pernod Ricard, Anheuser-Busch InBev, Heineken और Carlsberg जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों का कहना है कि अगर आयात शुल्क में राहत नहीं दी गई, तो उत्पादन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा और बाजार में आपूर्ति संकट और गहरा सकता है।

उद्योग के जानकारों के अनुसार, कच्चे माल की लागत में पहले ही करीब 15 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। यदि कंपनियां आयात के जरिए इस कमी को पूरा करने की कोशिश करती हैं, तो यह लागत 30 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। ऐसे में कंपनियों के लिए मुनाफा बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। स्थिति को और जटिल यह बनाता है कि भारत के अधिकांश राज्यों में शराब की कीमतें सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं। यानी कंपनियां अपनी बढ़ी हुई लागत को सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकतीं, जिससे उनका लाभ मार्जिन लगातार घटता जा रहा है।

इसी बीच Brewers Association of India ने भी सरकार से आयात शुल्क में राहत देने की मांग की है। एसोसिएशन के महानिदेशक विनोद गिरी का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में आयात ही एकमात्र विकल्प बचा है, क्योंकि घरेलू उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये की कमजोरी ने आयात को और महंगा बना दिया है, जिससे उद्योग पर दबाव कई गुना बढ़ गया है।

इस पूरे परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका असर केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। बीयर उद्योग हर साल सरकार को लगभग 5.52 अरब डॉलर का कर योगदान देता है। यदि उत्पादन और बिक्री में गिरावट आती है, तो यह सरकारी राजस्व को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में यह केवल एक उद्योग की समस्या नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक चिंता का विषय बन जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के सामने इस समय संतुलन बनाने की चुनौती है। एक ओर उसे घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करनी है, वहीं दूसरी ओर ऐसे संकट के समय में उद्योगों को राहत भी देनी है। यदि आयात शुल्क में अस्थायी छूट दी जाती है, तो इससे कंपनियों को राहत मिल सकती है और बाजार में आपूर्ति बनी रह सकती है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू उत्पादकों को नुकसान न पहुंचे।

बीयर उद्योग के सामने खड़ी चुनौतियां केवल आर्थिक नहीं हैं, बल्कि यह बदलते वैश्विक परिदृश्य का भी संकेत हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्र में होने वाला संघर्ष पूरी दुनिया के उद्योगों को प्रभावित कर सकता है। भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार के लिए यह एक सीख भी है कि उसे अपनी सप्लाई चेन को और मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना होगा, ताकि भविष्य में ऐसे संकटों का सामना बेहतर तरीके से किया जा सके।

फिलहाल, उद्योग की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। क्या सरकार आयात शुल्क में राहत देकर कंपनियों को राहत देगी, या फिर उद्योग को इसी दबाव में खुद को ढालना होगा—यह आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जब तक वैश्विक हालात सामान्य नहीं होते, तब तक बीयर उद्योग को इस कठिन दौर से गुजरना ही होगा।